letter2:letter1.qxd 9/26/2010 8:42 PM Page 124

प्रिय युवा बंधुओं और बहनों,

स्वतंत्र भारत के संविधान पर अंग्रेजों की शासन-प्रणाली छाई हुई है। अंग्रेजों का प्रशासनिक ढांचा, जो गुलामी में हम पर लादा गया था, उसे उसी रूप में हमने अपने लिए कायम रखा है।

स्वतंत्र भारत का शासन विभेदकारी ''पार्टी डेमोक्रेसी'' के नाम पर चलाया जा रहा है। यदि वस्तुस्थिति को समझें तो हमें अनुभव होगा कि स्वतंत्र भारत की राजनीति गुलामी के काल में अंग्रेजी शासन की नीति के समान ''डिवाइड एण्ड रूल'' की ही कार्बन-कॉपी है।

आजादी के 58 साल में अपवादस्वरूप केवल एक ही देशभक्तिपूर्ण कार्य हुआ है। वह है स्व. सरदार पटेल द्वारा 500 से अधिक देशी रियासतों का भारत में विलीनीकरण। इसके अतिरिक्त 1947 के बाद अपना समाज जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयवाद, संप्रदायवाद तथा पार्टीवाद के कारण अधिकाधिक विखरता जा रहा है। पार्टी आधारित शासन डेमोक्रेसी की विडंबना मात्र है। वह लोकाभिमुखी न होकर गुलामी के काल जैसा सत्ताभिमुखी है।

देश स्वतंत्र होने के बाद कोई भी पार्टी आम लोगों को स्वावलंबी व कर्तृत्ववान बनाने का काम नहीं करती। वे उन्हें हर आवश्यकता पूर्ति के लिए सरकार पर निर्भर रहने के लिए ही उकसाती हैं। रचनात्मक कार्य करने के स्थान पर गुलामी के दिनों जैसे ही आंदोलन, प्रदर्शन, धरने, हड़ताल और तोड़-फोड़ तक करने के लिए लोगों को भड़काती है। मानो, देश के नवनिर्माण का दायित्व केवल सरकार का है, विरोधी दलों और सामान्य जनों का नहीं है। फलस्वरूप, स्वतंत्र भारत में देशभक्ति एवं सामाजिक कर्तव्य की भावना जगाने का मूलभूत कार्य कोई नहीं कर रहा है। इस कारण, समाज में देशभक्ति की भावना लुप्त हो गई है। क्या यह स्वतंत्र भारत का अपेक्षित वातावरण है?

स्वतंत्रता संग्राम में कठोरतम यातनाएं सहने वाले स्व. जयप्रकाश जी ही एक ऐसे अग्रिम पंक्ति के नेता रहे, जिन्होंने स्वतंत्र भारत में अपने लिए कुछ भी लेना स्वीकार नहीं किया। अंतिम सांस तक वे देश और समाज की उन्नति के लिए लड़ते रहे। पार्टी डेमोक्रेसी भारत के लिए घातक बनेगी, यह उनका सुविचारित मत था।

उन्होंने अपने इतिहास तथा दुनिया भर की शासन-प्रणालियों का गहन अध्ययन कर भारत के लिए 'पार्टीलेस डेमोक्रेसी' को उपयुक्त माना था।

उनके इस सुझाव को किसी भी नेता या पार्टी ने तथा मीडिया ने पसंद नहीं किया। सभी ने 'पार्टीलैस डेमोक्रेसी' की कल्पना को अव्यवहारिक करार दिया। फलस्वरूप, जयप्रकाश जी राजनीतिक क्षेत्र में अनेक वर्षों तक उपेक्षा के शिकार बने रहे। किन्तु वे अपनी बात पर अडिग रहे। लगभग छह दशकों का अनुभव जयप्रकाश जी के विचार की महत्ता अनुभव कराता है।

पार्टी आधारित डेमोक्रेसी के कारण नेतागण देश को सुशासन देने के स्थान पर सत्ता-संघर्ष में ही उलझे हुए हैं। सत्ता पाने के लिए विधि-निषेध की उन्हें परवाह नहीं है। 'आयाराम-गयाराम' का मार्ग अपनाने में उन्हें संकोच नहीं है। क्षेत्रीयता, जातियता व सांप्रदायिकता के गठजोड़ से सिद्धांतहीन सरकारें बनाई जा रही हैं। राजनीति में अखित भारतीय जीवन-दृष्टि की अवहेलना हो रही है। केवल सत्ता पाने का लक्ष्य ही सर्वोपरि बना है।

1969 में सत्ता में बने रहने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने अपनी ही पार्टी कांग्रेस को खण्डित किया था। जब सत्ता पाना ही नेताओं तथा पार्टियों का लक्ष्य बना है तो सभी पार्टियां हर स्तर पर

देश स्वतंत्र होने के बाद कोई भी पार्टी आम लोगों को स्वावलंबी व कर्तृत्ववान बनाने का काम नहीं करती। वह उन्हें हर आवश्यकता पूर्ति के लिए सरकार पर निर्भर रहने के लिए ही उकसाती हैं।

गुटबाजी की शिकार बनी है। राजनीति आदर्श-विहीन बनी है। केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारें अस्थिर होने लगी हैं। भ्रष्टाचार अनियंत्रित हो गया है। अराजकता देशव्यापी बनी है। शासन से जनता का भरोसा उठ गया है।

स्वतंत्रता के 58 साल में किसी भी पार्टी की सरकार ने छह लाख गांवों में रहने वाली लगभग तीन-चौथाई आबादी की ओर देखा तक नहीं है। यह है हमारा प्रचलित लोकतंत्र। बेकारी और गरीबी की यातनाओं से त्रस्त होकर देश के अनेक भागों में लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। किन्तु देश के व्यवस्थावादी व सत्ताप्रेमी नेता अपनी सत्ता कायम रखने या पाने के लिए करोड़ों रुपयों के वारे-न्यारे कर रहे हैं। उन्हें देश और समाज की दुर्दशा की तनिक भी परवाह नहीं है। यह है पार्टी डेमोक्रेसी की दिशा और दशा।

गुजरात में श्री चिमनभाई पटेल की सरकार के भ्रष्टाचारी व अधिनायकवादी तौर-तरीकों से तंग आकर क्रुद्ध युवाओं ने सरकार के खिलाफ 'नवनिर्माण' आंदोलन प्रारंभ किया था। प्रांत भर के युवजनों ने एकजुट होकर अपने आंदोलन को दुर्दमनीय बनाया था। परिणामस्वरूप, चिमनभाई पटेल की सरकार का टिकना असंभव हुआ था।

गुजरात में युवा-शक्ति के स्वप्रेरित उभार से जयप्रकाश जी का युवा-शक्ति पर विश्वास द्विगुणित हुआ। उन्होंने ''समग्र-क्रांति'' द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में आमूलचूल परिवर्तन प्रारंभ करने के लिए यही समय उपयुक्त समझा।

1974 में बिहार के भ्रष्ट शासन के खिलाफ उन्होंने अपना स्वास्थ्य खराब होते हुए भी ''समग्र-क्रांति'' अभियान की शुरुआत की।

जयप्रकाश जी की किडनी काम करने से इंकार कर चुकी थीं। हर हफ्ते उन्हें डायलिसिस करवाना अनिवार्य हुआ था। अधिक आयु के कारण कमजोरी भी बढ़ रही थी। फिर भी देश की गंभीर हालत ने उन्हें बेचैन बनाया था। वे अपनी बीमारी व कमजोरी की परवाह किए बिना गांव-गांव का दौरा करने लगे। युवक-युवतियां तपस्वी जयप्रकाश जी की व्याकुलता और हिम्मत देखकर ''समग्र-क्रांति'' में जी-जान से जुटने लगे। बिहार के विधायकों से युवक-युवतियां दोस्तियां बनाकर गांव-गांव में ''समग्र-क्रांति'' के जुलूस निकालने लगे थे। विद्यार्थी परिषद् के युवकों ने भी इसमें योगदान दिया। बिहार की सम्पूर्ण युवा-शक्ति ''समग्र-क्रांति'' अभियान में उमड़ पड़ी।

जयप्रकाश जी ने 14 नवम्बर, 1974 को पटना में विधान सभा भवन पर प्रदर्शन की घोषणा की। सरकार ने जगह-जगह बैरिकेड खड़े कर प्रदर्शनकारी विधान सभा भवन न पहुंचें, इसका जोरदार बंदोबस्त किया था। किन्तु उभरती युवा-शक्ति के जोश का तूफान इतना प्रबल था कि सारे बैरिकेड बेकार सिद्ध हुए।

हजारों की संख्या में युवक-युवतियां जयप्रकाश जी के नेतृत्व में विधान सभा भवन की ओर बढ़ रहे थे। इनमें किसी भी राजनीतिक पार्टी या नेता का योगदान नहीं था। पुलिस के अश्रुगैस और लाठी चार्ज के बावजूद जुलूस तितर-बितर न होकर आगे ही बढ़ता गया। युवक-युवतियों के सर फटकर लहू-लुहान होते देख जयप्रकाश जी स्वयं आगे बढ़े। उन पर भी लाठी प्रहार करने में पुलिस ने संकोच नहीं किया। थके-मांदे जयप्रकाश जी घायल अवश्य हुए, किन्तु प्रभु कृपा से उनके प्राण बच गए।

जवानों के इस विशाल हुजूम में से किसी एक ने भी पुलिस पर पथराव नहीं किया। तोड़-फोड़ की एक भी घटना नहीं घटी। यह थी तपस्वी जयप्रकाश जी के व्यक्तित्व की महिमा।

पटना में जयप्रकाश जी पर हुए लाठी-प्रहार की खिंचा देश भर में प्रतिध्वनित हुई। जयप्रकाश जी के

पार्टी आधारित डेमोक्रेसी के कारण नेतागण देश को सुशासन देने के स्थान पर सत्ता-संघर्ष में ही उलझे हुए हैं। सत्ता पाने के लिए विधि-निषेध की उन्हें परवाह नहीं है।